तथा उसके क्या कारण हैं और इसके पुनर्गठन के बाद क्या-क्या लक्ष्य प्राप्त किए जाएंगे; और

(ङ) क्या सरकार इसके लिए सहमत हो गई है; यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम): (क) तथा (ख) जी हां। पिछले तीन वर्षों के दौरान एस०टी०सी० द्वारा प्राप्त कर पूर्व लाभ का वर्षवार ब्यौरा नीचे दिया गया है:—

वर्ष	करोड़ रु० में
1992-93	26.93
1993-94	29.97
1994-95	41.04

(ग) से (ङ) अब तक एस०टी०सी० के जरिए सरणीकृत कई मदों के निर्यात और आयात के सरणीयन को समाप्त कर देने के फलस्वरूप सरकार एस०टी०सी० के कार्य संचालन को उदारीकृत अर्थव्यवस्था और प्रतिस्पर्धी वातावरण के अनुरूप बनाने की जरूरत की पुनरीक्षा कर रही है। अपने व्यापारिक क्रिया-कलापों को व्यापक बनाने के एक भाग के रूप में, खासकर गैर-सरणीयन क्षेत्र में, एस०टी०सी० प्रमुख कार्यक्रमों का विविधिकरण कर रही है जिसका उद्देश्य निम्नलिखित कार्य-योजनाएं अपना कर अगले पांच वर्षों के भीतर 5,000 करोड़ रु० का वार्षिक कारोबार हासिल करना है:—

—सीधे खरीद और बिक्री पर जोर देना;

—विदेशों में विपणन नेटवर्क को मजबूत करना;

—सी आई एस देशों के साथ अधिक व्यापार करना;

—संयुक्त उद्यम स्थापित करना;

—ओ जी एल आयात करना;

—घरेलू व्यापार बढ़ाना।

चीनी नीति में परिवर्तन

1366. **श्री सुन्दर सिंह भंडारी**: क्या **खाद्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गन्ना उत्पादकों और उपभोक्ताओं के लाभ के लिए चीनी नीति में क्या परिवर्तन किए गए हैं;

(ख) गन्ना उत्पादकों के लिए कौन-सी नई व्यवस्थाएं की गई हैं;

(ग) चीनी की उपलब्धता बढ़ाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं; और

(घ) गन्ने के अन्य उपयोगों संबंधी योजना क्या है?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह): (क) से (ग) 1994-95 मौसम में चीनी और गन्ने का बहुत अच्छा उत्पादन होने और 1995-96 मौसम में भी बहुत अच्छा उत्पादन होने के संकेत मिलने के कारण चीनी नीति में कोई व्यापक परिवर्तन नहीं किया गया है। तथापि, 1.1.1996 से लेवी चीनी के आवंटन में संशोधन किया गया है जो 1986 की जनसंख्या की बजाय 1991 की जनसंख्या पर आधारित है। इससे सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिये 2.16 लाख मीटरी टन की अतिरिक्त मात्रा उपलब्ध होगी।

(घ) चीनी के अलावा, गन्ने का इस्तेमाल गुड़ और खण्डसारी के उत्पादन में भी हो रहा है। अच्छे उत्पादन को ध्यान में रखते हुए गुड़ (नियंत्रण) आदेश, 1994 को प्रभावी नहीं पाया गया और इसे रद्द कर दिया गया।

Non-payment of minimum wages to workers

1367. SHRI JANARDAN YADAV: *Will the Minister of* LABOUR *be* pleased to state:

(a) whether workers in various parts of the country are not being paid the minimum wages fixed;

(b) if so, whether Government have set up a Central Industrial Relation Machinery for the implementation of the Minimum Wages Act;

(c) if so, when was this set up and the average total amount being spent by Government on this; and

(d) what is the total number of cases investigated by this machinery so far and number of cases found to be irregular and names of the States in respect of which maximum and minimum irregular cases have been detected respectively?

THE MINISTER OF LABOUR

(SHRI G. VENKATSWAMY): (a) The Minimum Wages Act which provides for payment of wages at rates not below those fixed under the Minimum Wages Act is being strictly enforced by the Central Government.

(b) Central Industrial Relations Machinery (CIRM) has been set-up for prevention and settlement of industrial disputes, labour inspections, enforcement of various labour laws including Minimum Wages Act in industries/ employments for which appropriate Government is the Central Government. It also carries out certain functions relating to verification of membership of trade unions in the Country.

(c) CIRM was set up in April, 1945. Average amount being spent annually during 1992-93 to 1994-95 is Rs. 6.3 crores, (total of Plan and Non-plan expenditure). A statement is enclosed (*see* below).

(d) Information regarding number of inspections, irregularities detected, irregularities regarding less payment, claim cases filed and decided, prosecution cases filed and decided for the period from 1990 to 1994 is given in a tabulated from attached herewith (Annex.) [*See* Appendix 175, Annexure No. 38].

As regards, the States with maximum and minimum number of irregularities, it is stated that the State of Orissa, leads in the number of irregularities detected while the minimum number of irregularities were detected in the state of Kerala.

Statement

Details showing expenditure incurred by CIRM during the period from 1992-93 to 1995-96

(Rupees in thousands)

Year	Non-plan	Plan	Total
1. 1992-93	4,95,03	66,95	5,61,98
2. 1993-94	5,53,92	83,93	6,37,85
3. 1994-95	5,83,29	93,51	6,76,80
4. 1995-96 (upto Sept., 95)	3,70,86	50,39	4,21,25

Average Expenditure for the first three year from 1992-93 to 1994-95 = Rs. 625,54 thousand or say Rs. 6.3 crore.

Number of land oustees from Orissa Coal Fields

1368. SHRI RAHASBIHARI BARIK:
SHRI BHAGABAN MAJHI:

Will the Minister of COAL be pleased to state:

(a) the number of land oustees on different coal fields in Talcher, Anugul and other parts of Orissa;

(b) whether Government have taken steps to provide jobs and compensation to the affected families and their kith and kin;

(c) if not, the number of cases which have not been settled so far; and

(d) the details therefor with action taken in the matter?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COAL (SHRI JAGDISH TYTLER): (a) Number of land losers identified in various on going projects/coalfields in Orissa are as under:—

1. Talcher Coalfields — 4840